

भारत तथा अमेरिका के बीच बढ़ती असहमति

संदर्भ

सगिापुर में शांगरी-ला वार्ता में अपने भाषण में एक प्रमुख वदिश नीतिविकृतव्य के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के खुले और सुरक्षित हृदि-प्रशांत क्षेत्र पर "साझा दृष्टिकोण" की बात की। फरि भी उनका कथन अमेरिकी रक्षा सचवि जेम्स मैटसि द्वारा इसी समारोह में बोले गए कथन से काफ़ी अलग था, इन बातों से स्पष्ट होता है कनिई दल्लि और वाशगिटन अब इस मुद्दे के साथ-साथ कई अन्य मुद्दों पर बहुत अधिकि समय तक सहमतिबिनाए रखने के लयि तैयार नहीं हैं।

बढ़ता फ़ासला

- श्री मोदी ने हृदि-प्रशांत महासागर क्षेत्र (हृदि तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लयि अमेरिका द्वारा प्रयुक्त कयिा गया शब्द) को एक प्राकृतिक भू-क्षेत्र के रूप में संबोधति कयिा, न करिणनीतिकि, जबकि श्री मैटसि ने भारत-प्रशांत को "प्रायोरिटी थयिटर" और "सैन्य अधिकार के लयि [अमेरिका की] व्यापक सुरक्षा रणनीतिका सबसेट", (अब इसका नाम बदलकर इंडो-प्रशांत कमांड रखा गया है) के रूप में उल्लेखति कयिा।
- जब श्री मोदी ने अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के अच्छे संबंधों को समान माप में संदर्भति कयिा तो श्री मैटसि ने हृदि-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों का मुकाबला करने का वादा कयिा, और इस वर्ष जनवरी में जारी अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीतिका उल्लेख कयिा जो चीन और रूस दोनों को अपने क्रॉसहेयर में दुनयिा की दो "संशोधनवादी शक्तियों" (revisionist powers) के रूप में देखता है।
- एक साल पहले, मोदी सरकार ने अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते दबाव, वशिष रूप से पोस्ट-डोकलाम के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिवि (BRI) को चुनौती दी और साथ ही भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलयिा के एक चतुरभुज समूह को समर्थन दे रही थी।

वर्तमान परदृश्य

- आज, डोकलाम मुद्दे को दफना दयिा गया है, BRI पहले की तरह चतिा का वषिय नहीं है, और मालदीव और नेपाल के लयि सरकार के गैर-टकराववादी दृष्टिकोण से पड़ोस में चीन पर एक नरम नीतिका संकेत मलित्ता है।
- इस बीच, श्री मोदी ने वुहान बैठक के द्वारा चीनी राष्ट्रपतिशी जनिपगि के साथ घनषिठ संबंधों और चीन के साथ रशिते को रीसेट करने का प्रयास कयिा।
- क्वाड गठन (Quad formation) जो सगिापुर में आज अपनी दूसरी आधिकारिक बैठक आयोजति कर रहा है, को भी कम महत्त्व दयिा गया है।

भारत द्वारा अमेरिका तथा जापान के साथ समुद्री अभ्यास से इनकार

- भारत ने इस वर्ष जून में अमेरिका और जापान के साथ समुद्री अभ्यास में शामिल होने के लयि ऑस्ट्रेलयिाई अनुरोध को खारजि कर दयिा और नौसेना प्रमुख एडमरिल सुनील लांबा ने पछिले महीने स्पष्ट रूप से कहा किक्वाड में "सैन्यीकरण" की कोई योजना नहीं थी।
- इसके वपिरीत रूस तथा चीन की अगुवाई वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के देशों के साथ सैन्य अभ्यास जसिका आयोजन कगिदाओ में होगा, में शामिल होने के लयि भारत की स्वीकृतिसे वाशगिटन में उत्पन्न व्याकुलता को कोई भी समझ सकता है।

शखिर-सम्मेलनों का युग

ऐसी दुनयिा जहाँ नेताओं के बीच शखिर सम्मेलन ने महान रणनीतिका बदल दयिा है वहाँ दृश्यमान शक्तियिँ आज भी स्पष्ट हैं।

- यदि अनौपचारिक और औपचारिक शखिर सम्मेलन के साथ-साथ SCO, ब्रिक्स और जी-20 बैठकों की गणना की जाए, तो भारतीय

- प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादमिर पुतिन से वर्ष के अंत तक चार-पाँच बार मलि होंगे ।
- इसके विपरीत, भारतीय और अमेरिकी रक्षा मंत्रियों और वदेश मामलों के मंत्रियों की आगामी 2+2 बैठक को निर्धारित करने में लगभग आधा साल बीत चुका है ।
 - व्यापार संरक्षणवाद जो हाल के महीनों में कई मुद्दों पर एक दूसरे को विश्व व्यापार संगठन में ले गए हैं, स्पष्ट रूप से भारत और अमेरिका के बीच वरिध का दूसरा बड़ा मुद्दा है ।

दोनों देशों के बीच बढ़ता विवाद

दोनों देशों के बीच कई विवादों में वृद्धि हुई है, जैसे -

- अमेरिका के नए स्टील और एल्युमीनियम टैरिफि ।
- H1B पेशेवर वीजा में प्रस्तावित कटौती और H4 पति/पत्नी के वीजा रद्द करना ।
- डेयरी और पोर्क उत्पादों के अमेरिकी निर्यात के प्रतिरोध पर भारत के टैरिफि ।
- चकित्सा उपकरणों पर भारतीय मूल्य में कटौती ।
- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा अमेरिकी कंपनियों पर भारतीय सर्वर पर डेटा स्थानीयकरण के नियम लागू करना ।

हार्ले-डेवडिसन विवाद

- भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते विवादों के संदर्भ में हार्ले-डेवडिसन मोटरसाइकलियों का एक छोटा सा मामला है, जहाँ रश्ते में थोड़ी सी दरार होनी चाहिये थी लेकिन इस मामले ने काफी गंभीरता से भारत और अमेरिका के बीच विवाद को बढ़ा दिया ।
- जब ट्रंप ने पछिले साल फरवरी में हार्ले के अधिकारियों और संघ प्रतिनिधियों के लिये घोषणा की कि वह अन्य देशों को इसका "लाभ लेने" पर रोक लगाएंगे तो उस समय नई दिल्ली में किसी ने भी इस घोषणा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया ।
- साल भर के दौरान श्रीमान ट्रंप इस मांग को लेकर और अधिक मुखर होते गए जिसमें मोदी के साथ वाशिंगटन तथा मनीला में हुई दो मीटिंग भी शामिल हैं, जिसमें इसने भारत से अपने टैरिफि को 75 से 100 प्रतिशत तक कम करने के लिये कहा था, उल्लेखनीय है कि अमेरिका इंडियन रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकल के आयात पर शून्य टैरिफि लगाता है ।
- श्री मोदी ने अमेरिकी चिंताओं को समायोजित करने की कोशिश की और यहाँ तक कि इस साल 8 फरवरी को श्री ट्रंप को फ़ोन कर यह आश्वासन भी दिया कि टैरिफि 50% तक कम किया जाएगा । श्रीमान ट्रंप ने इस व्यापार वार्ता को सार्वजनिक कर दिया था ।
- वाशिंगटन के अधिकारियों का कहना है कि यदि भारत अपनी दरों को कम करना चाहता है, तो वाणिज्य के अन्य कर्षेत्रों में इसके बड़े लाभ दिखाई देंगे, जबकि नई दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि श्री ट्रंप ने मोदी के प्रस्ताव को सार्वजनिक किया है तथा आगे इस दर को और अधिक कम करना असंभव होगा ।

भारत-अमेरिका संबंधों के लिये बड़ी चुनौतियाँ

- समन्वित भारत-अमेरिका दृष्टिकोण के लिये सबसे बड़ी चुनौती अब नए अमेरिकी कानून Countering America's Adversaries Through Sanctions Act तथा ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने के कारण और अधिक प्रतिबंधों का खतरा उत्पन्न हो गया है ।
- रूस से रक्षा हार्डवेयर पर इसकी उच्च निर्भरता और ईरान में इसकी काफी ऊर्जा हतियों के कारण, अमेरिका की इन दोनों कार्रवाइयों का भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है ।
- विशेष रूप से रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली हासिल करने की भारत की योजना लटिमस परीक्षण के सामान हो जाएगी जिसमें यह देखना शेष है कि क्या भारत और अमेरिका अपने मतभेदों को समाप्त कर पाएंगे या नहीं ।
- स्पष्ट रूप से इस तरह के बड़े सौदों के कारण होने वाले मतभेदों को निरणय लेने से बहुत पहले ही हल कर लेना चाहिये था । हालाँकि इस बात के बलिकुल भी संकेत नहीं हैं कि ट्रंप प्रशासन तथा मोदी सरकार को ऐसा करने से पहले एक दूसरे को विश्वास में लेने की आवश्यकता है ।

अमेरिकी प्रतिबंधों का वरिध

- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की एस-400 समझौते की घोषणा और वदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा इस महीने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खुला वरिध किया गया ।
- सचचाई यह है कि गत वर्ष के दौरान ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध बनाना वाशिंगटन में साउथ ब्लॉक और भारतीय दूतावास दोनों के लिये मुश्किल रहा है, क्योंकि 30 से अधिक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों ने या तो पदत्याग दिया है या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है ।
- साथ ही यह भी स्पष्ट है कि भारत-अमेरिका समीकरण पछिले साल के समान संतुलन की स्थिति में नहीं है जब मोदी और ट्रंप द्वारा "2+2" वार्ता की घोषणा की गई थी ।
- सुश्री स्वराज, सुश्री सीतारमण और उनके अमेरिकी समकक्षों ने 6 जुलाई को वाशिंगटन में आयोजित होने वाली बैठक के लिये अपने

कार्यों में कटौती की है।

‘2+2’ संवाद क्या है?

- यदि दो देशों के बीच एक साथ ही दो-दो मंत्रस्तरीय वार्ताएँ आयोजित की जाएँ तो इसे 2+2 संवाद मॉडल का नाम दिया जाता है।
- भारत और अमेरिका के बीच संवाद को नया रूप देने के लिये नियमित वार्ता का एक ऐसा ढाँचा विकसित किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी और मज़बूत होगी।
- इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि हिंदि-प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में भारत-अमेरिका मिलकर अपनी भूमिका निभाएँ।
- प्रस्तावित संरचना के तहत अब भारत और अमेरिका के बीच ‘2+2’ व्यवस्था के तहत नियमित रूप से मंत्रस्तरीय वार्ता होती रहेगी और दोनों देशों के रक्षा एवं वदेशि सचिवों के बीच सतत् संपर्क बना रहेगा।
- मंत्रस्तरीय वार्ता का नया तंत्र शुरू कर हिंदि-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ने से दोनों देशों के बीच रणनीतिक विचार-विमर्श और बढ़ेगा।

नष्कष

चीन और हसिक चरमपंथ हिंदि-प्रशांत क्षेत्र में दीर्घकाल में कई चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं, जबकि किसी भी क्षेत्र की समृद्धि सुरक्षा पर नरिभर करती है। भारत के लिये इस संवाद के साथ आगे बढ़ना एक ‘बैलेंसिंग एक्ट’ के समान होगा, जिसमें संतुलन साधने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि राजनीति में एक सप्ताह की अवधि एक लंबा समय है तो भू राजनीति में वर्तमान समय अनंतकाल के समान है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-america>

